"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 11, Issue: 06, Nov. – Dec. 2024 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 6.323

मुद्रास्फीति : भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती।

राजेश कुमार

सहायक प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अटरू (बारां) राजस्थान, भारत

अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार, मुद्रास्फीति तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य कम होता है तथा मुद्रास्फीति कम होने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अभी हाल के 2–3 वर्षों में बढ़ती मुद्रास्फीति से ना केवल उपभोक्ता वर्ग परेशानहै बल्कि साथ ही व्यावसायिक फर्में भी ऋण की उच्च लागत से झूज रही हैं तथा उनके लिए बैंकों से ऋण लेना पहले से महँगा हो गया है जिससे फर्में नया निवेश नही कर पा रही है। इससे फिर महंगाई घटने की बजाय बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का एक मूख्य उद्धेश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना भी है जो 4% के स्तर पर निर्धारित है तथा इसमें +2 % का विचलन हो सकता है अर्थात यह 2% से लेकर 6% के स्तर पर रह सकती है। परन्तु अभी के वर्षो में RBI को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखना पड़ रहा है जिससे उद्योग जगत को काफी निराशा हाथ लगी है। इससे कही न कही आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ा है।

यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगभग **2% की** सतत वार्षिक दर की वृद्धि होती है तो इस कीमत वृद्धि को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति अति मुद्रास्फीति अथवा सरपट मुद्रास्फीति, जिसमें एक सप्ताह अथवा इससे भी कम अल्प समय में कीमत वृद्धि 80% अथवा इससे अधिक हो सकती है, से भिन्न होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति डगमग चाल वाली मुद्रास्फीति, जिसमें कीमतों में मध्यवर्ती गति से वृद्धि होती है, से भी भिन्न होती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित नही किया जाए तो वह डगमग चाल भरकर अति मुद्रास्फीति का भयानक रूप धारण कर सकती है। ऐसी स्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति का तीव्र गति से ह्रास होता है।

मुद्रास्फीति के कारण :–

1. **माँग प्रेरित अथवा बेशी मांग मुद्रास्फीति :–**

इस संबंध में नट विक्सैल तथा जे.एम.कीन्स दोनो ने ही मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेशी माँग की उपस्थिति से सम्बद्ध किया है जबकि प्रतिष्ठित अर्थशाखियों ने इसके लिए मुद्रा पूर्ति को उत्तरदायी बताया था।

2. **लागत प्रेरित मुद्रास्फीति :–**

यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का आरंभ उत्पादन लागत अथवा वस्तुओं की पूर्ति कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। वस्तुओं कि उत्पादन लागत में वृद्धि उत्पादन साधनों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण होती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय व्युत्पन्न मुद्रास्फीति :–

1974 के पश्चात पैट्रोल एवं पैट्रोल पदार्थो की अन्तराट्रीय कीमतो में सतत् वृद्धि होने के कारण विश्व के देशो में मुद्रास्फीति की घटना उत्पन्न हो गई है।

भारत में हालियां मुद्रास्फीति की प्रवृति :–

वर्ष 2023 में भारत की मुद्रास्फीति दर वैश्विक औसत से 1.4 % अंक कम थी। वर्ष 2020 से, देशो को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। वित्त वर्ष 2023 में, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPR) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से प्रभावित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम रही। बाहरी रूप से रूस–युक्रेन युद्ध ने, जबकि घरेलू स्तर पर, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला । हांलाकि, मई 2022 से व्यापक रूप से मौद्रिक नीति के अन्तर्गत रेपो दर को मई 2022 में 4 % से 250 आधार अंको की वृद्धि करके फरवरी 2023 में 6.5 % तक बढाकर प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने पर ध्यान केन्द्रित किया है । इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023 में देखी गई लगातार और स्थिर कोर मुद्रास्फीति जून 2024 में घटकर 3.1 % हो गई।

आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2023-24

चार्ट III.5: महामारी के बाद से खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में सबसे कम थी

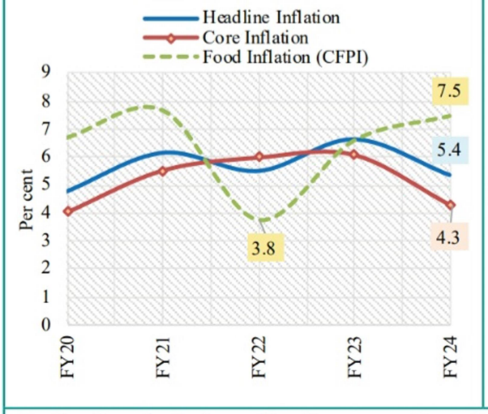

चार्ट III.6: हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति

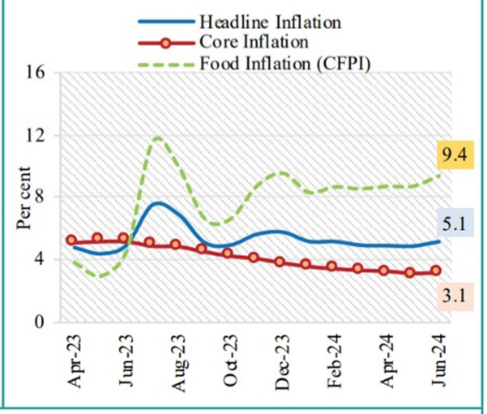

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चुंकि वैखिक ऊर्जा मूल्य सूचकांक में वित्त वर्ष 24 में तीव्र गिरावट आयी, जिससे खुदरा ईधन मुद्रास्फीति भी कम रही। केन्द्र सरकार द्वारा LPG, पेट्रोल और डीजल के लिए मूल्य कटौती की घोषणा से LPG और पेट्रोलियम उत्पाद मुद्रास्फीति में कमी आयी। अगस्त 2023 में, देशभर के सभी बाजारों में घरेलू LPG सिलेन्डर की कीमत 200 रू0 प्रतिसिलेन्डर कम कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप LPG मुद्रास्फीति दर सितंबर 2023 से डिफलेशन जोन में रही है। इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित फुटकर मंहगाई दर सितंबर 2023 में गिरकर 5.02 % पर आ गई। यह जून 2023 के बाद सबसे कम है। जूलाई में खुदरा मंहगाई दर 7.44 % थी जबकि अगस्त में यह दर 6.83 % पर रही । मार्च 2024 में, गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर 100 रू0 की कमी पुनः एक बार कर दी गई थी। इसी तरह मार्च 2024 में केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रू0 प्रति लीटर की कमी की। इससे इनकी खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में डिफलेशन जोन में चली गई। इसके

अतिरिक्त 2023 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में गिरावट आयी, जिससे आयातित मुद्रास्फीति चैनल के माध्यम से ऊर्जा, धातुओं, खनिजों और कृषि वस्तुओं में मूल्य दबाव कम हो गया। कम ईधन और कोर मुद्रास्फीति ने वित्त वर्ष 24 में खाद्य कीमतों में अस्थिरता के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट सुनिश्चित किया।

NSO मंहगाई के आंकड़े 1114 शहरी और 1181 ग्रामीण क्षैत्रों से जुटाता है। सिंतम्बर 2023 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) गिरकर 188.3 % के स्तर पर आ गया जो कि अगस्त में 192.5 था। सरकार ने उडद और तुअर दाल के टैक्स फ्री आयात को एक वर्ष यानी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है ताकि अन्य लोगों को सस्तीदाल उपलब्ध कराई जा सके। इससे पहले रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क को 17.5 % से घटाकर 12.5 % किया गया था। सरकार की और से उठाये गया इन कदमों का उद्धेश्य खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश अगाना है नवम्बर में ,खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.7 % हो गई जो कई परिवारों पर बोझ डाल रही है।

पिछले दो वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है ऐसा जलवायु परिर्वतन के कारण माना जा रहा है। गर्म हवांए, असमान मानसून वितरण , बैमोसम वर्षा , ओलावृष्टि, मूसलाधार वर्षा और एतिहासिक शुष्क स्थितियों से कृषि क्षैत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा। इसलिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8% से बढ़कर वित्तवर्ष 23 में 6.6 % और वित्त वर्ष 2024 में 7.5 % हो गई।

चार्ट III.20: खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान (%)

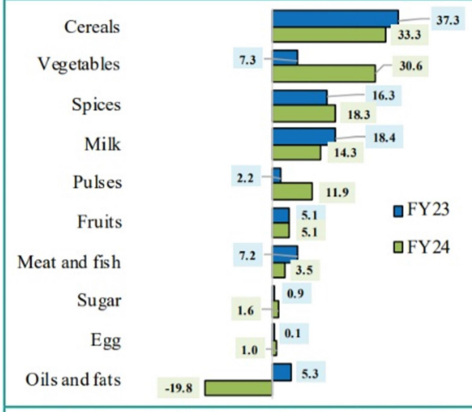

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण की गणना

चार्ट III.21: सब्जियों, दालों और मसालों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर (%)

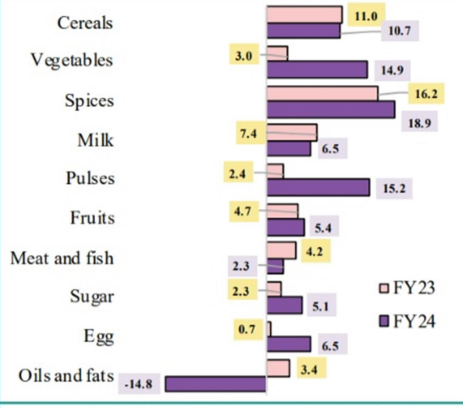

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

प्रमुख खाद्य वस्तुओं में कीमत वृद्धि के कारण :–

सब्जियों और दालों की उत्पादन संभावनाएं विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित हुई। जुलाई 2023 में टमाटर की कीमतों में वृद्धि फसल उत्पादन में मौसमी बदलाव सफेद मक्खी के संक्रमण जैसी क्षैत्र–विशिष्ट फसल रोगों और देश के उत्तरी भाग में मानसून के जल्दी आगमन के कारण हुई थी। भारी बारिश के कारण अलग अलग क्षेत्रों में रसद सेवाओं में भी व्यवधान आया। प्याज की कीमतों में तेजी कई कारकों के कारण आयी है जिसमें पिछले कटाई सत्र के दौरान बारिश का रबी प्याज की गुणवक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव होना, खरीफ सत्र के दौरान बुवाई में देरी, लंबे समय सूखे की अवधि से खरीफ उत्पादन प्रभावित होना और अन्य देशो द्वारा किए गए व्यपार संबंधी उपाय शामिल है।

दालों, विशेष रूप से तुअर की कीमतों में वृद्धि पिछले दो वर्षो में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण कम उत्पादन की वजह से हुई है। रबी सीजन में धीमी बुवाई और दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी परिवर्तन के कारण उडद का उत्पादन प्रभावित हुआ था। पिछले रबी सीजन की तुलना में चने का क्षैत्र और उत्पादन भी कम रहा ।

वर्ष 2023 की शुरूआत से दुध की कीमत में बढोतरी रही है। हालांकि यह वित्त वर्ष 24 के अंत तक कम हो गई। हालांकि सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थो की प्र्याप्त आनूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री निदिष्ट दुकानों में खुदरा बिक्री और समय पर आयात सहित त्वरित कावाई की। इसके अतिरिक्त गरीबों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान प्रदान करती है को जनवरी 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षो की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

अगर मई 2024 से खाद्य मुद्रास्फीति और खुदरा महँगाई दर की बात करें तो मई 2024 में खाद्य मंहगाई बीते साल की तूलना से तीन गुना बढ़ी है। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक मई 2024 में 8.69 % पर पहुंच गया जो मई 2023 में 2.91 % था। कमोडिरी रिसर्च फर्म के मुताबित बीते साल की तुलना में खाद्य तेल के दाम 30 % और दालों के दाम औसतन 20 % अधिक है। इतना ही नही घर ,खर्च मे करीब 24 % हिस्सेदारी रखने वाले किराने के सामान भी आसमान छूने लगे है। बीते दो महीने में साबुन हेयर ऑइल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम 2 से 17% बढ़ गए है।

3 महीने में 10 सबसे जरूरी चीजों के दाम 10 % बढ़े

कमोडिटि	27 जून 2024	26 मार्च 2024	बदलाव
चीनी	44	44	0.0 %
आटा (गेंहू)	32	31	3.23 %
उड़द दाल	143	138	3.62 %
तुअर दाल	177	157	12.74 %
मूँगफली तेल	209	207	0.97 %
सरसो तेल	148	139	6.47 %
सोया तेल	128	129	-0.78 %
टमाटर	40	38	5.26 %
आलू	33	25	32 %
प्याज	50	33	51.52 %
औसत वृद्धि			**10.46 %**

बैंक ऑफ बड़ोदा के इकोनॉमिस्ट अदिति गुप्ता और डीपान्विता मजूमदार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की वजह से अप्रेल–जून तिमाही में टमाटर 37.6 % प्याज 89.4 % और आलू 81.1 % मंहगे हो चुके है। कंज्यूमर रिसर्च फर्म कैटा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च के तीन महीनों में आम भारतीय परिवार ने ग्रॉसरी (किराना, सब्जी, दूध, अंडे आदि) पर 49,148 रू खर्च किए यानी हर महीने एक आम भारतीय परिवार किराने पर 16,400 रू ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके लिए बढ़ती लागत खराब मौसम और सरकारी हस्तक्षेप बड़ी वजह है। प्याज के निर्यात पर 40 % शुल्क लगने से किसानो ने खेती कम कर दी, क्योकि उन्है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से आय की उम्मीद नही रही। इधर जून में खाद्य मँहगाई दर मई के 8.69 % के मुकाबले बढ़कर 9.36 % पर पहुँच गई

जो दिसम्बर 2023 के बाद सबसे अधिक है। इसी प्रकार खुडरा मंहगाई दर भी जून में 5.08 % पर पहूँच गई जो मई में 4.75% पर थी। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के बढ़ने का कारण दाल की कीमतों में सालाना आधार पर 17% तो सब्जियों की कीमतों में 29 % का बढ़ना रहा है। जुलाई में खुदरा महँगाई दर 3.54% के स्तर पर पहूँच गई। यह 59 माह यानी लगभग 5 साल का सबसे नीचा स्तर था। साथ ही खाद्य महँगाई दर में भी बडी गिरावट आई है और यह जुलाई में 5.42 % पर आ गई जो जून में 9.36 % बढ़ी थी। जूलाई में खुदरा व खाद्य महँगाई दर बढ़ने की रफ्तार भले ही सालाना आधार पर घटी है, पर जून 2024 के मुकाबले जुलाई में खुदरा महँगाई 1.4 % और खाने–पीने के सामान के दाम 2.8% बढ़े। जुलाई 2024 में सालाना आधार पर महँगाई दर में यह गिरावट हायर बेस के कारण है क्योंकि पिछले साल की समान अवधि में देश में महँगाई काफी बढ़ गई थी। जुलाई 2023 में खुदरा महँगाई दर 7.44% और खाद्य महँगाई दर 11.51 % बढ़ी थी। पिछले साल के मुकाबले इस जुलाई खुदरा महँगाईदर 3.54 % बढ़ी है जबकि जून में पिछले साल के मुकाबले 5.09% बढ़ी थी। एक बार फिर अगस्त में खुदरा महँगाई दर 3.65 % रही जबकी खाद्य कीमत सूचकांक 5.66% पर रही जो जुलाई में 5.42% पर थी। वही सितंबर में खुदरा महँगाई दर 9 महीने के उच्चतम स्तर तक बढ़ गई थी। तथा उपभोक्ता खाद्य महँगाई दर भी 9.24% तक बढ़ गयी जो अगस्त के 5.66 % से अधिक थी। अक्टूबर में एक बार फिर महँगाई ने 14 महीने का उच्चतमस्तर प्राप्त कर लिया तथा खुदरा महँगाई दर 6.2% पर रही। इससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद करने वाले उद्योग जगत को फिर से निराशा हाथ लगी है। जबकि अक्टूबर में खाद्य महँगाई दर 10.87% पर पहुँच गई हालांकी नवम्बर में खूदरा महँगाई दर थोडा घटाकर 5.48% पर आई जो अक्टूबर में 6.21% पर थी, साथ ही खाद्य वस्तुओं की महँगाई नवम्बर में 10.87 से घटकर 9.04% पर आ गई। दिसम्बर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खूदरा महँगाई चार माह के निचले स्तर 5.22% पर आयी जो कुछ राहत का संकेत है।

भारत में मुद्रास्फीति के कारणों की जाँच के लिए कि क्या मुद्रास्फीति माँग में वृद्धि के कारण बढ़ रही है या पूर्ति के कारण, इसके लिए CMIE ने उपभोक्ता व्यय के आँकडों का उपयोग करते हुए एक लेख प्रकाशित किया । इसके तहत इस संस्था ने पाया कि जब माँग आधारित मुद्रास्फीति होती है तो इसमें कीमतों तथा मात्राओं में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है अर्थात दोनो में वृद्धि होती है, और यदि माँग में कमी होती है तो दोनो में कमी होती है। इसके विपरीत पूर्ति आधारित मुद्रास्फीति में कीमत तथा मात्राओं में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है जिसके तहत पूर्ति में कमी होने पर कीमतों में वृद्धि होती है जबकि पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमतों में कमी होती है। उपरोक्त कार्यविधि का उपयोग करते हुए जनवरी 19 से मई 2023 तक के आँकड़ों का विश्लेषण सुझाते है कि सब्जियां, तेल और वसा, दूध, अण्डे, दालें और चीनी जैसी श्रेणियों लगातार पूर्ति आधारित बाधाओं को अनुभव कर रही है जबकि गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पाद और स्वास्थय आधारित वस्तुएं मुख्यतः माँग आधारित कारकों से प्रभावित है।औसत रूप से, जनवरी 2019 से मई 2023 के दौरान CPI हेडलाईन की 55 % मुद्रास्फीति के लिए आपुर्ति आधारित कारक उत्तरदायी थे। इसके विपरित माँग आधारित कारको ने COVID-19 महामारी के दौरान हेडलाईन मुद्रास्फीति में कमी प्रदर्शित की है जो 2019 में 41.5 %से घटकर 2020 में 27.1% तक हो गई । हालांकि कोविड–19 के प्रतिबंधो में ढील तथा रूस, युक्रेन संघर्ष के बाद माँग में रूक रूक कर हूई वृद्धि ने माँग आधारित मुद्रास्फीति ने मंहगाई को बढ़ाने में महन्ता प्रदशित की है जो अप्रेल 2022 में एकदम ऊँचाई पर पहुँच गई। जनवरी 2019 से मई 2023 के संपूर्ण समय के दौरान माँग आधारित मँहगाई का योगदान 31 % के आसपास था।

मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय :–

1. मोद्रिक नीति :– इसके तहत रिजर्व बैंक ब्याज दरे बढ़ा सकता है इससे उधार लेना मँहगा होगा, जिससे फर्मे कम निवेश करेंगी। ब्याज दरें बढ़ने से लोगो द्वारा भी बचतों मे वृद्धि होगी। स्वयं का मकान खरीदने के लिए लोगो को ज्यादा गिरवी रखना पडेगा जिससे उनके पास कम उपभोग्य आय रहेगी तथा इससे वे कम खर्च कर पायेंगे।
2. एक ऊँची ब्याज दर ऊँची विनिमय दर का कारण बनेगी। इससे आयात सस्ते होगे तथा निर्यातों की माँग कम होगी क्योंकि वे पहले से कम प्रतिस्पर्धी होगें जिससे उनकी घरेलू उपलब्धता बढ़ने से उनकी घरेलू पूर्ति में वृद्धि होगी तथा इससे घरेलू कीमतों में कमी होगी।
3. राजकोषीय नीति :– सरकार कर दरें बढ़ायेगी जैसे आयकर तथा वैट और साथ ही खर्चो में कटौती करेगी। इससे मांग घटेगी।
4. कीमत नियंत्रण :–सरकार कीमत राशनिंग के तहत कीमतों पर नियंत्राण कर सकती है।
5. आपूर्ति परक नीतियाँ :– इन नीतियों से अर्थव्यवस्था में आपूर्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए ज्यादा लोचदार श्रम बाजार नीतियाँ मुद्रास्फीति दबावों को कम करने में सहायता देती है।
6. विनिमय दर नीति :– एक देश महँगाई को कम करने के लिए स्थिर विनिमय दर अपना सकता है।

निष्कर्ष :–

मुद्रास्फीति प्रबंधन में महामारी और उसके बाद के भू राजनैतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियाँ पेश की। महामारी के कारण आपूर्ति श्रंखला में व्यवधान और बढ़ते वैश्विक संघर्षों के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने भारत को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया । इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23 में कोर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य कीमते प्रभावित हुई थी। इन घटनाओं का निवल प्रभाव वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में उच्च मुद्रास्फीतिक दबाव था। विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई और सरकार द्वारा तैयार की गई सुविचारित व्यापार नीति उपायों, उचित उत्पादन वृद्धि, वित्त वर्ष 24 में कोर मुद्रास्फीति को चार वर्ष के निचले स्तर तक कम करने में सहायक रही। इसके अलावा, मध्यावधि से दीर्धावधिक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण का निर्धारण मूल्य निगरानी तंत्रों और बाजार आसूचना के सुदृढीकरण के साथ साथ दालों और खाद्य तेलों जिसके लिए भारत की आयात निर्भरता काफी हद तक है, जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढानें के संकेद्रित प्रयासों द्वारा किया जाएगा।

बुक संदर्भ :–

1. समष्टि अर्थशास्त्र सातवाँ संस्करण लेखक :– एम.सी. वैश्य **VIKASH Publishung House Page 461 - 467**
2. आर्थिक समीक्षा – 2023 –2024 Page 75, 77–78, 83–84
3. दैनिक भास्कर – 13 अक्टूबर 2023 की प्रति
4. दैनिक भास्कर – 13 मार्च 2024 की प्रति
5. दैनिक भास्कर – 07 अप्रेल 2024 की प्रति
6. दैनिक भास्कर – 28 जून 2024 की प्रति
7. राजस्थान पत्रिका – 15 अक्टूबर 2024 की प्रति
8. राजस्थान पत्रिका – 14 नवम्बर 2024 की प्रति
9. दैनिक भास्कर – 15 जनवरी 2025 की प्रति
10- Tools of eradicate of inflation - Economic Help website